एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी ।

**मध्य प्रदेश स्थित पेंच तापीय विद्युत स्टेशन का गैर-सरकारी औद्योगिक एकक को सौंपा जाना**

1861. **श्री अजीत जोगी :**
**कुमारी आलिया :**

क्या **विद्युत और गैर-पारम्परिक** ऊर्जा स्रोत मंत्री 26 नवम्बर, 1991 को राज्य सभा में अतारांकित प्रश्न 468 के दिए गये उत्तर को देखेंगे और यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मध्य प्रदेश से पेंच तापीय स्टेशन का कार्य किन-किन शर्तों पर अभी हाल में किसी गैर-सरकारी औद्योगिक एकक को दिया अथवा सौंपा गया है; और

(ख) इस प्रकार से उत्पन्न की गई बिजली की क्या दर वसूल की जायेगी तथा इसके उपभोक्ता कौन होंगे ?

**विद्युत और गैर-पारम्परिक ऊर्जा स्रोत मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री कल्पनाथ राय)** : (क) और (ख) मध्य प्रदेश सरकार ने सूचित किया है कि यथा-संशोधित विद्युत (प्रदाय) अधिनियम, 1948 के प्रावधानों और इस संबंध में भारत सरकार द्वारा जारी मार्गदर्शी सिद्धांतों के अनुसरण में उनके द्वारा एक निजी क्षेत्र फर्म को पत्र जारी किया गया है जिसमें जिला छिन्दवाड़ा के चौरासा गांव में 2×210 मे.वा. के पेंच ताप विद्युत केन्द्र की स्थापना, इसके प्रचालन एवं अनुरक्षण संबंधी कार्य उक्त फर्म को सौंपा गया है। मध्य प्रदेश सरकार ने दरों एवं सप्लाई के संबंध में शर्तों सहित किसी प्रकार की शर्तों के बारे में निर्णय नहीं किया है।

**Canada's Performance in Chamera Hydro-Electric Project**

1862. SHRI S. MADHAVAN: Will the Minister of POWER AND NON-CONVENTIONAL ENERGY SOURCES be pleased to state:

(a) whether the Central Electricity Authority has sent report about the dismal performance of the Canadians in the statge I of Chamera Hydro-electric Project and if so, what are the details thereof;

(b) whether a high level enquiry committee was set up to probe into the collapse of transmission towers brought from Canada and if so, what are the details thereof; and

(c) whether Government have decided to entrust Chamera II stage to the same company inspite of their failures in Chamera I stage and if so, what are the reasons therefor?

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF POWER AND NON-CONVENTIONAL ENERGY SOURCES (SHRI KALP NATH RAI): (a) As part of its monitoring function, the Central Electricity Authority has been periodically monitoring and reviewing the progress of execution of various power projects in the country, including the Chamera H.E. Project, Stage-I which is being executed by the National Hydro-electric Power Corporation with financial and technical assistance from Canada. Though there has been some delay in the completion of the project, the CEA has not sent any report attributing the same to the Canadians.

(b) The NHPC set up a Committee headed by a General Manager to examine the failure of the Transmission towers brought from Canada. The possibilities, whether the failure could have been caused due to manufacturing defect or by the unprecedented high velocity of wind, are being looked into.

(c) The Government have not taken any decision so far about availing of Canadian assistance for the Stage-II of Chamera H.E. Project.

**कृषि हेतु दी जाने वाली बिजली के लिये अधिक शुल्क लिया जाना**

@1863. **डा० जिनेन्द्र कुमार जैन :**
**श्री रणजीत सिंह :**

क्या विद्युत और गैर-पारम्परिक ऊर्जा स्रोत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 10 नवम्बर, 1991 के इंडियन एक्सप्रेस में "एग्रीकल्चर सेक्टर-मिनिमम टैरिफ और इलैक्ट्रिसिटी प्रपोज्ड" शीर्षक के अन्तर्गत प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है; यदि हां, तो क्या यह सच है कि सरकार ने कृषि क्षेत्र को दी जाने वाली बिजली की राज सहायता प्राप्त दरों को बढ़ाने का निर्णय किया है;

(ख) क्या इस निर्णय के परिणामस्वरूप कृषि उत्पादन की लागत में वृद्धि हो जाने की सम्भावना है; और

(ग) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में सरकार की प्रतिक्रिया क्या है ?

विद्युत और गैर पारम्परिक ऊर्जा स्रोत मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री कल्पनाथ राय) : (क) सितम्बर, 1991 में आयोजित विद्युत मंत्रियों के सम्मेलन में हुई आम सहमति के अनुपालन में, हाल ही में राज्यों को 50 पैसे/कि०वा० घं० को न्यूनतम कृषि विद्युत टैरिफ के निर्धारण के लिए अनुरोध किया गया है।

(ख) और (ग) विभिन्न फसलों/राज्यों के लिए उत्पादन की कुल लागत पर प्रस्तावित वृद्धि का नाम-मात्र प्रभाव पड़ेगा।

---

@पूर्वत: अतारांकित प्रश्न 1486, 6 दिसम्बर, 1991 से स्थानांतरित।

**देश में बिजली का भारी संकट**

1864. **श्री अजीत जोगी :** क्या विद्युत और गैर-पारम्परिक ऊर्जा स्रोत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि देश बिजली के भारी संकट का सामना कर रहा है;

(ख) यदि हां, तो प्रत्येक राज्य की मांग को पूरा करने हेतु बिजली का उत्पादन बढ़ाने के लिए क्या कदम उठाये जाने का विचार है;

(ग) आठवीं पंचवर्षीय योजना के लिए इस सम्बन्ध में ब्यौरा क्या है;

(घ) देश में बिजली की बढ़ती हुई मांग को देखते हुए क्या कोई दीर्घकालिक नीति बनाने का विचार है;

(ङ) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है; और

(च) विद्युत उत्पादन को प्रभावित करने वाले पर्यावरण सम्बन्धी कारणों को देखते हुए क्या कोई नई सकारात्मक पर्यावरणीय नीति बनाये जाने की सम्भावना है ?

विद्युत और गैर पारम्परिक ऊर्जा स्रोत मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री कल्पाथ राय) : (क) अप्रैल, 91–अक्तूबर, 91 की अवधि के दौरान देश में लगभग 8% ऊर्जा की कमी थी।

(ख) देश में विद्युत उत्पादन में सुधार लाने हेतु किए जा रहे विभिन्न उपायों में ये शामिल हैं :– पुराने यूनिटों के नवीकरन एवं आधुनिकीकरण संबंधी कार्य करना, संयंत्र सुधार कार्यक्रमों को हाथ में लेने के लिए बिजली बोर्डों की सहायता करना, अपेक्षित मात्रा और गुणवत्ता वाला कोयला सप्लाई करना, प्रचालन और अनुरक्षण कार्मिकों को प्रशिक्षण देना और पारेषण और वितरण प्रणालियों को सशक्त बनाना।